गुरिंदर ओबेरॉय © ए.पी. - डब्ल्यू डब्ल्यू पी.

अमेरिकी राजदूत डेविड सी. मल्फ़र्ड और भारत के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में 4 जुलाई को समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हाथ मिलाते हुए।

फ़ुलब्राइट-नेहरू स्कॉलरशिप समझौते पर हस्ताक्षर

राजदूत डेविड सी. मल्फ़र्ड और भारत के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने 4 जुलाई को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत और अमेरिका के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान को और मज़बूत कर दिया।

इस समझौते से भारत 58 वर्ष पुराने फ़ुलब्राइट आदान-प्रदान कार्यक्रम का बराबर का हिस्सेदार तो बना ही है, भारत में इसके लाभार्थियों की संख्या भी दोगुनी हो गई है।

इस अवसर पर राजदूत मल्फ़र्ड ने कहा, ''हम दोनों ने अपने लम्बे समय से चले आ रहे समझौते में नई ऊर्जा का संचार करने के अवसर का लाभ उठाया है... आज हमने जो किया है उसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में दोनों देशों के हजारों युवाओं को अमूल्य लाभ प्राप्त होंगे।''

नई भागीदारी को प्रतिबिम्बित करते हुए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अध्ययनवृत्तियां अब फ़ुलब्राइट-नेहरू स्कॉलरशिप के नाम से जानी जाएंगी। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों गैरी एकरमैन, रस कार्नाहन, शीला जैक्सन-ली, एल ग्रीन, टैडियस मैक्कॉटर और रैंडी न्यूगबॉअर की उपस्थिति में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हस्ताक्षर हुए। यह समझौता विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों को एक बंधन में बांधने वाले सशक्त और फलते-फूलते जन सम्बन्धों का प्रतीक है और दोनों देशों द्वारा शिक्षा और विद्वानों के आदान-प्रदान को दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करता है।

स्कॉलरशिप को प्रायोजित करवाने वाले सेनेटर जे. विलियम फ़ुलब्राइट के नाम से जाने जाने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिकी कांग्रेस ने 1946 में ''शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्रों में विद्यार्थियों के आदान-प्रदान से अंतरराष्ट्रीय सौहार्द'' बढ़ाने के लिए की थी। यह 155 देशों में संचालित हो रहा है। 2 फ़रवरी 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजदूत लॉय हैंडरसन द्वारा पहले आदान-प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से 5,000 से अधिक भारतीय अमेरिका में और 9,800 से अधिक अमेरिकी भारत में फ़ुलब्राइट अध्येताओं के रूप में अध्ययन कर चुके हैं।

अमेरिकी राजदूत लॉय हैंडरसन (बाएं) और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 फ़रवरी 1950 को भारत के लिए फ़ुलब्राइट समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद (दाईं और बैठे हुए) और अमेरिकी एवं भारतीय अधिकारी भी मौजूद थे।